REPORT OF THE JOINT COMMITTEE ON OFFICES OF PROFIT

SHRI DILIPBHAI PANDYA (Gujarat): Sir, I lay on the Table, a copy (in English and Hindi) of the Nineteenth Report of the Joint Committee on Offices of Profit.

DISCUSSION

Re. Filling up the vacancies in SC/ST, OBC and Minorities Commissions

श्री नरेश अग्रवाल (उत्तर प्रदेश): उपसभापति जी, राम गोपाल जी ने रूल 267 के तहत नोटिस दिया है, पहले इनको सुन लिया जाए। ...**(व्यवधान)**...

श्री सतीश चंद्र मिश्रा (उत्तर प्रदेश): सर, पहले इनको सुन लिया जाए। ...**(व्यवधान)**...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: If all of you stand up, what do I do? ...(*Interruptions*)...

श्री नरेश अग्रवाल: सर, एक-एक करके बुलवा लीजिए। ...**(व्यवधान)**...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Ram Gopalji, you have given notice. Please take only two minutes. I am not allowing notice under Rule 267, but since you have given notice, I am allowing you to speak.

प्रो. राम गोपाल यादव (उत्तर प्रदेश): सर, मैं अपने लिए जिम्मेदार हूँ कि मैं तीन मिनट या दो मिनट बोलूंगा, लेकिन और लोग कितना बोलेंगे, उसके लिए मेरी जिम्मेदारी कुछ भी नहीं है।

सर, ऐसा है कि यह मामला पहले भी उठ चुका है, लेकिन अब यह मामला बहुत व्यापक हो गया है। इस सरकार के रहते तीन बहुत महत्वपूर्ण आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग, अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग और माइनॉरिटी कमिशन, ये सब खाली पड़े हैं। इनके द्वारा इनमें कोई नियुक्ति नहीं की जा रही है। इनके जरिए लोगों को जो राहत मिलनी चाहिए, वह नहीं मिल पा रही है यानी इनसे जुड़ी हुई 80 से 85 परसेंट आबादी को किसी तरह की कोई राहत नहीं मिल पा रही है। कैबिनेट ने अभी जो नया निर्णय लिया है, जिसके बारे में मैंने उस दिन मामला उठाया था, उसमें असली बात यह सामने आई है कि बैकवर्ड क्लास कमीशन का जो नाम बदला है, उसके पीछे यह है कि मंडल कमीशन ने सर्वे करके जो यह निश्चित किया था कि ये जातियां बैकवर्ड हैं, उनको बिल्कुल nullify कर दिया जाएगा और अब नए सिरे से तय होगा कि कौन-सी जातियां बैकवर्ड हैं और कौन नहीं हैं और संसद उसको तय करेगी कि किसको इनमें से निकालना है और किसको रखना है। ये यही स्थिति अनुसूचित जाति आयोग और अनुसूचित जनजाति आयोग में पैदा कर देंगे। हम सब लोग यह जानते हैं कि किन-किन जातियों को टारगेट करके उन्हें उनमें से निकालने की * इस गवर्नमेंट की है।

सर, माइनॉरिटी कमीशन पूरी तरह से खाली पड़ा हुआ है। इसके लिए इनकी न मंशा है, न इच्छा शक्ति है और न ये इसे किसी तरीके से करना चाहते हैं। सरकार की इस नीति को लेकर देश में बड़े पैमाने पर लोगों के मन में जबर्दस्त गुस्सा है, नाराजगी है और अगर इसका कोई

*Expunged as ordered by the Chair.